पीएनबी के मुनाफे में 11.1 फीसदी की बढ़ौतरी

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में पीएनबी का मुनाफा 11.1 फीसदी बढ़कर 230.1 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में पीएनबी का मुनाफा 207.2 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में पीएनबी की ब्याज आय 6.9 फीसदी बढ़कर 3,989 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में पीएनबी की ब्याज आय 3,730.8 करोड़ रुपए रही थी। तिमाही दर तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में पीएनबी का ग्रॉस एनपीए 13.31 फीसदी से घटकर 12.11 फीसदी रहा है। तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में पीएनबी का नेट एनपीए 8.44 फीसदी से घटकर 7.55 फीसदी रहा है। रुपए में पीएनबी के एनपीए पर नजर डालें तो तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में ग्रॉस एनपीए 57,630 करोड़ रुपये से घटकर 57,519.4 करोड़ रुपए रहा है। तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में पीएनबी का नेट एनपीए 34,570.2 करोड़ रुपए से घटकर 34,075.7 करोड़ रुपए रहा है। तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में पीएनबी की प्रोविजनिंग 2,440.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,466.7 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछली साल इसी तिमाही में प्रोविजनिंग 2,562.2 करोड़ रुपएये रही थी। सालाना आधार पर तीसरी तिमाही में पीएनबी की लोन ग्रोथ में 17 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है।

राजकोषीय घाटा बढ़ने से कुल अर्थव्यवस्था पर असर नहीं : मूडीज

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। वित्त वर्ष 2018-19 का बजट राजकोषीय मजबूती व वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है और राजकोषीय घाटे को सीमित करने की राह से छोटे-मोटे भटकाव का अर्थव्यवस्था की कुल ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यह राय जताई है। सरकार ने 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़कर 3.3 प्रतिशत कर दिया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। मूल लक्ष्य क्रमश: 3 और 3.2 प्रतिशत का था। मूडीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी विलियम फॉस्टर ने कहा, ''संशोधित राजकोषीय मजबूती का लक्ष्य पिछली रूपरेखा से कुछ अधिक है लेकिन इससे भारत की कुल राजकोषीय मजबूती पर असर नहीं होगा।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्ज से जी.डी.पी. अनुपात को घटाकर 40 प्रतिशत पर लाने के मध्यम अवधि का लक्ष्य सांवरेन क्रेडिट परिदृश्य की दृष्टि से सकारात्मक है। मूडीज ने बयान में कहा कि मार्च, 2019 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत के बजट में राजकोषीय मजबूती और वृद्धि के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है। मूडीज के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विश्लेषक जॉन रैकोथने ने कहा कि इस बजट से कार्पोरेट क्षेत्र के साथ बीमा क्षेत्र को भी फायदा होगा। मूडीज का अनुमान है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने में सफल रहेगी।

बिल देने वाली 123 कंपनियों के पते फर्जी

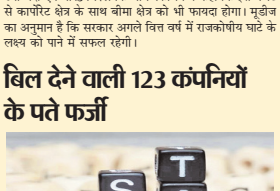

लुधियाना 6 फरवरी (ए)। जी.एस.टी. बिल घोटाले का मामला उलझता जा रहा है। विभाग के सामने 123 कंपिनयां ऐसी सामने आई हैं, जिन्होंने माल की बिक्री दिखाकर उसके बिल जारी किए। लेकिन किस बिल पर किस पार्टी को माल बेचा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अधिकारियों ने जब बिल देने वाली कंपनियों के पतों पर छानबीन शुरू की तो 123 कंपनियों के पते फर्जी निकले। बिलों पर दिए गए पतों पर कोई भी कंपनी का दफ्तर या फैक्टरी नहीं मिली। बीते दिनों एडीशनल कमिश्नर सौरव राज ने लुधियाना में केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक से कुछ संदिग्ध कंपनियों की बैंक स्टेटमैंट ली थी। उनमें सैंकड़ों ऐसी कंपनियां मिलीं, जिन्होंने करोड़ों की ट्रांजैक्शन की हुई हैं। इसी के आधार पर एडीशनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स पवन गर्ग को जांच आगे बढ़ाने के लिए अधिकार पत्र लिखित में दिया। अधिकारियों ने फुर्ती दिखाते हुए 3 दिन के भीतर हालांकि शनिवार व रविवार की छुट्टी होने के बावजूद 123 कंपनियों की जांच की। इन सबके पते फर्जी निकले। यानी जिन कंपनियों ने माल बेचने के बिल काट रखे हैं उनके सबके पते जाली निकले। इन पतों पर किसी भी कंपनी का आफिस नहीं मिला। माल किस कंपनी को बेचा उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही। ध्यान रहे कि पंजाब केसरी ने पहले ही 123 कंपनियों के जाली होने के बारे में जानकारी दी थी और जांच में भी यही पाया गया।

दुबई फिर से दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

दुबई 6 फरवरी (ए)। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथॉरिटी ने कहा कि वर्ष 2017 में करीब 8.82 करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ उसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वर्ष 2016 में हवाई अड्डे पर 8.36 करोड़ यात्रियों ने आवागमन किया था। दुबई हवाई अड्डे के सी.ई.ओ. पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष 2018 में यात्रियों के आवागमन का यह आंकड़ा 9.03 करोड़ को छू सकता है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे पहले वर्ष 2014 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना था।

फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदने की रेस में ऐमजॉन और अलीबाबा

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। फ्यूचर ग्रुप में पहले हिस्सेदारी कौन खरीदेगा- ऐमजॉन या अलीबाबा ग्रुप? ऐसा लग रहा है कि अभी ऐमजॉन इस रेस में आगे चल रहा है। फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी ने दो हफ्ते पहले अमेरिका में ऐमजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस से मुलाकात की थी। इसमें दोनों के बीच संभावित गंठबंधन पर चर्चा हुई। देश में ऑर्गेनाइड फूड और ग्रॉसरी मार्केट के एक तिहाई हिस्से पर फ्यूचर ग्रुप का कब्जा है। बियानी कुछ समय पहले चीन गए थे, जहां उनकी मुलाकात अलीबबा के अधिकारियों से हुई थी। वह चीन की कंपनी का बिजनस मॉडल समझने वहां गए थे। बियानी उस मॉडल को भारत में आजमाना चाहते हैं।

ऐमजॉन के साथ बियानी की बातचीत से वाकिफ तीन सूत्रों में से एक ने बताया, फ्यूचर ग्रुप कंपनी में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने की सोच रहा है, जबकि

ऐमजॉन भारत में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मौजूदगी भी चाहता है। खासतौर पर उसकी दिलचस्पी ग्रॉसरी रिटेलिंग सेगमेंट में इस रणनीति को आजमाने की है। सूत्र ने बताया, दोनों कंपनियों के संस्थापकों की मुलाकात ऐमजॉन के सिएटल बेस्ड हेडक्वॉर्टर में हुई। दोनों ने भारतीय रिटेल मार्केट पर बातचीत की। इस पर चर्चा हुई कि किस तरह के अलायंस से दोनों कंपनियों को फायदा हो सकता है। एक सूत्र ने बताया कि बियानी के पास स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के मामले में बहुत विकल्प नहीं हैं क्योंकि कुछ ही ग्लोबल प्लेयर्स के पास भारत में बिजनस बढ़ाने की भूख और उसके लिए पैसा है। उन्होंने कहा कि वहीं ऐमजॉन के नजरिए से देखें तो फ्यूचर ग्रुप उसके लिए अच्छा पार्टनर हो सकता है। बियानी के ग्रुप के पास ऑफलाइन रिटेल मॉडल है। फूड और नॉन-फूड आइटम्स का बियानी ने मुनाफे वाला बिजनस खड़ा किया है। देश के बड़े हिस्से में फ्यूचर ग्रुप की मौजूदगी है। उसकी ताकत अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज, लगेज और फुटवियर सेगमेंट में है। ऐमजॉन को शायद यह भी लग रहा है कि अलीबबा या सॉफ्टबैंक के फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदने से उसकी चुनौतियां भारत में बढ़ सकती हैं। इस खबर के लिए ईमेल से पूछे गए सवालों का फ्यूचर ग्रुप और अलीबबा ने जवाब नहीं दिया, जबकि ऐमजॉन ने कहा कि वह अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं देती। एक रिटेल ऐनालिस्ट ने कहा कि ऐमजॉन अपनी इन्वेस्टमेंट यूनिट के जरिए भारत की रिटेल कंपनी में निवेश कर सकता है। वह उसी तरह से फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी ले सकती है, जिस तरह से उसने शॉपर्स स्टॉप में 5 प्रतिशत लिया है। भारत में ऐमजॉन ने सेबी के पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए वह देश की किसी रिटेल कंपनी में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी ले सकता है।

भारती एयरटेल में 92649 करोड़ निवेश करेगी सिंगटेल

कोलकाता 6 फरवरी (ए)। सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (सिंगटेल) देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए वह भारती एयरटेल की होल्डिंग कंपनी भारती टेलीकॉम लिमिटेड में 2,649 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगी। यह हिस्सेदारी एक प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू के जरिए बढ़ाई जाएगी। भारती एयरटेल इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने के लिए करेगी।

सिंगटेल ने सोमवार को बताया, सिंगटेल इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट्स को 310 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्राइस पर भारती टेलीकॉम में 8.54 करोड़ नए इक्विटी शेयर अलॉट किए जाएंगे। सिंगटेल ने बताया कि यह ट्रांजैक्शन मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके लिए भारती टेलीकॉम के शेयरहोल्डर्स की अनुमति जरूरी होगी। भारती टेलीकॉम एक अनलिस्टेड कंपनी है। टेलीकॉम मार्केट में कुछ समय पहले प्रवेश करने वाली रिलायंस जियो इंफोकॉम को टक्कर देने के लिए टैरिफ घटाने के चलते भारती एयरटेल को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने बताया कि वह सिंगटेल से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए करेगी। दिसंबर 2017 के अंत में भारती एयरटेल पर 91,714 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड डेट था।

इस इनवेस्टमेंट के साथ भारती टेलीकॉम में सिंगटेल की हिस्सेदारी 47.17 पर्सेंट से बढ़कर 48.90 पर्सेंट हो जाएगी। सुनील मित्तल की इस कंपनी में भारती एंटरप्राइसेज की हिस्सेदारी 50.1 पर्सेंट है। इसके नतीजे में भारती एयरटेल में सिंगटेल का स्टेक 0.9 पर्सेंट बढ़कर 39.5 पर्सेंट हो जाएगा। बीएसई पर सोमवार को भारती एयरटेल का शेयर 4.2 पर्सेंट की तेजी के साथ 439.50 रुपये पर बंद हुआ। सिंगटेल के इस इनवेस्टमेंट को भारती एयरटेल में उसके लंबी अवधि के लिए विश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। सिंगटेल के सीईओ, आर्थर लैंग ने कहा, भारत में अभी उथल-पुथल चल रही है, लेकिन हम एयरटेल में अपने इनवेस्टमेंट को लेकर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं और एयरटेल की मार्केट लीडर के तौर पर मजबूत स्थिति है।

वेतनभोगी, कारोबारी लोगों के कर भुगतान में असमानता : अधिया

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। वेतनभोगी वर्ग तथा कारोबार जगत द्वारा किए जाने वाले आयकर भुगतान में असमानता है। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली 7 लाख कम्पनियों में से करीब 50 प्रतिशत शून्य या नकारात्मक आय दिखाती हैं। अधिया ने कहा कि सरकार फूलप्रूफ प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले कर भुगतान में असमानता दूर करने का प्रयास कर रही है। वित्त सचिव ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने और उससे पहले नोटबंदी के बाद से करदाता आधार बढ़ा है। भारत को एक कर अनुपालन वाला समाज बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल और इन्वॉयस मिलान से इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कर

चोरी रोकने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) की बजट बाद बैठक को संबोधित करते हुए अधिया ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में वेतनभोगी लोग कारोबारी लोगों की तुलना में अधिक कर अदा कर रहे हैं। आकलन वर्ष 2016-17 में 1.89 करोड़ वेतनभोगी लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए और कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए का कर दिया। प्रति व्यक्ति वेतनभोगी करदाता यह औसतन 76,306 रुपए बैठता है। वहीं 1.88 करोड़ व्यक्तिगत कारोबारी करदाताओं और पेशेवरों ने कुल 48,000 करोड़ रुपए का कर अदा किया।

अलग कीमत के लिए साबित करनी होगी स्टेंट की श्रेष्ठता

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। स्टेंट कीमतों में संशोधन को लेकर स्टेंट निर्माताओं और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) के बीच हुई बैठक में बहुराष्ट्रीय स्टेंट निर्माताओं ने एक बार फिर से दवा नियामक से स्टेंट के लिए खास मूल्य निर्धारण पर विचार करने का आग्रह किया है। बैठक में शामिल इन अधिकारियों ने बताया कि एन.पी.पी.ए. ने कहा है कि वह उसी स्थिति में स्टेंट के लिए अलग-अलग कीमतों की अनुमति देगा जब वे स्टेंट की श्रेष्ठता साबित करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि बॉस्टन साइंटिफिक और मेडट्रोनिक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वर्गीकरण पर जोर दिया है, लेकिन घरेलू निर्माताओं ने एन.पी.पी.ए. को बताया है कि वे कीमतों के संदर्भ में ऊंची सीमा चाहते हैं क्योंकि मौजूदा कीमत सीमा उपयुक्त नहीं है।

जेपी इन्फाटेक के बिडिंग प्रोसेस पर रोक नहीं लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। जयप्रकाश एसोसिएट्स के कंपनी के लिए संभावित लेंडर्स से बिड मंगाने पर इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल पर रोक लगाने के प्रपोजल को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अस्वीकार कर दिया। जेपी इंफाटेक के देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बिड मंगाई जानी हैं। कोर्ट दिल्ली की चित्रा शर्मा और 23 अन्य होम बायर्स की अपने वकील ऐश्वर्य सिन्हा के जरिए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही जेपी इंफाटेक की पैरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपने वकील अनुपम लाल के जरिए कहा कि बिडिंग का प्रोसेस 4 और 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। इनमें से पहले ऑर्डर में कोर्ट ने जेपी इंफाटेक के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसेस से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई थी, जबकि दूसरे ऑर्डर में उसने ड्रॉक्स को एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्लान जमा करने का निर्देश दिया था। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने कहा कि उसने कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2,000 करोड़ रुपये में से 550 करोड़ रुपये पहले ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास जमा करवा दिए हैं। कंपनी का कहना था कि वह होम बायर्स के हितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इस वजह से बिडिंग का प्रोसेस रोका जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल बिडिंग प्रोसेस को जारी रखेंगे। बैड लोन की रिकवरी के लिए जेपी इंफाटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से नियुक्त ड्रॉक्स ने अपने निर्यात्रण में लिया है। जैन ने 27 अक्टूबर, 2017 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जेपी के मामले के समाधान के लिए कंपनियों ने आवेदन मंगाए थे। इसके लिए बिड देने की अंतिम तारीख 5 नवंबर थी। जेपी इंफाटेक की पूरी तरह या हिस्सों में खरीदने के लिए 18 एंटिटीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। रिजॉल्यूशन प्लान को कंपनी के क्रेडिटर्स और NCLT से स्वीकृति मिलना जरूरी है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरे (कोर्ट के सहायक) पवन श्री अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि ड्रॉक्स की वेबसाइट पर अभी तक 900 होम बायर्स ने रजिट्रेशन कराया है और इन होम बायर्स से 40-45 करोड़ रुपये के क्लेम मिले हैं।

लैंको इंफा के लिए 4 कंपनियों ने बोली लगाई

मुंबई 6 फरवरी (ए)। कई पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की होल्डिंग कंपनी लैंको इंफ्राटेक को खरीदने में ऐसी चार कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है जो नामचीन नहीं हैं। इससे लेंडर्स में यह डर समा गया है कि लोन के निपटारे के लिए उनके सामने यादा हेयर कट की डिमांड रखी जा सकती है। मामले के जानकार दो सूत्रों ने बताया कि कंपनी के चार बिडर्स में ओपीजी ग्रुप, प्रेम एनर्जी, गोयल ग्रुप और दिवा ग्रुप शामिल हैं।

लैंको इंफाटेक पर फाइनैंशियल और ऑपरेशन क्रेडिटर्स का कुल 50,652 करोड़ रुपये का दावा है। कंपनी के खिलाफ बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। डूबड्डू बैंक पिछले साल अगस्त में कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास ले गया था। लेंडर्स का कहना है कि लैंको इंफाटेक के रिजॉल्यूशन प्लान को कामयाबी उसकी सब्सिडरीज के टर्नअराउंड पर डिपेंड करती है। एक लेंडर ने कहा, ओपीजी ग्रुप तब से लैंको को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है जब इसका मामला एनसीएलटी के पास नहीं ले जाया गया था। लेकिन बाकी तीन एंटिटीज-प्रेम एनर्जी, गोयल ग्रुप और दिवा ग्रुप नामचीन नहीं हैं। लैंको इंफाटेक लिस्टेड कंपनी है जिसमें मधुसूदन राव की अगुवाईवाले प्रमोटरों की 58.5% हिस्सेदारी है और बाकी पब्लिक शेयरहोल्डिंग है। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल सावन गोडियावाला ने कंपनी के वास्ते रिजॉल्यूशन प्लान के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाते वक्त एलिजिबेंट्स के लिए किसी भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बताई है। फाइनैंशियल क्रेडिटर्स ने कंपनी पर 45,263 करोड़ रुपये का दावा किया है जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के 5389 करोड़ रुपये का दावा मंजूर किया गया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की तरफ से आए यादातर क्लेम लैंको की दूसरी कंपनियों के हैं। रिलेटेड पार्टीज के टोटल 7164 करोड़ रुपये के 12 क्लेम हैं। लेकिन रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने अब तक सिर्फ 4324 करोड़ रुपये के रिलेटेड पार्टी क्लेम्स ही स्वीकार किए हैं। 91318 करोड़ का सबसे बड़ा रिलेटेड पार्टी क्लेम लैंको बबंध पावर और दूसरा लैंको विदर्भ थर्मल का है जिसने 975 करोड़ रुपये का दावा किया है।

खाली व बिना बिके मकानों पर मिलेगी आयकर में छूट

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किफायती आवास क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा देने से इसे सस्ता ऋण, कर छूट और विदेशी तथा निजी पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। पुरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सस्ते आवासों को प्रोत्साहन देने के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने किफायती आवास क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा दिया है। इससे आवास क्षेत्र को सस्ता ऋण, कर छूट और विदेशी पूंजी एवं निजी पूंजी का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए खाली और बिना बिके मकानों पर एक वर्ष तक आयकर में छूट भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भू-संपदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016, भू-संपदा निवेश ट्रस्ट, बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, मकानों के ऋण दरों में कमी, वस्तु एवं सेवाकर और भूमि सुधार किए हैं।

वारंटी पीरियड में वसूला चार्ज, अब कंपनी देगी मुआवजा

बेंगलुरू 6 फरवरी (ए)। वारंटी पीरियड के अंदर रहते हुए फोन रिपेयरिंग के लिए चार्ज लेने पर फोन निर्माता कम्पनी शाओमी को यहां की सिटी कंज्यूमर कोर्ट ने एक ग्राहक को मुआवजा देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कम्पनी और सर्विस सैंटर को फोन की कीमत और मुकदमे पर आया खर्च 10,999 रुपए देने का आदेश दिया है। एच.एस.आर. लेआऊट में रहने वाले मधुसूदन ने 24 मार्च, 2015 को ई-कॉमर्स वैबसाइट फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपए की कीमत का शाओमी रैडमी 2 हैंडसैट लिया था। 8 अक्तूबर को उनके फोन का डिस्प्ले खराब हो गया। उनके फोन पर कॉल्स रिसीव हो रही थी और फोन वाइब्रेट भी कर रहा था। वह फोन कोरमंगला के टी.वी.एस. इलैक्ट्रॉनिक्स ले गए जो एक अधिकृत सर्विस सैंटर था। वहां उन्हें कहा गया कि 2550 रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने स्क्रीन बदलने के लिए कह दिया। 2 दिन बाद उन्हें सर्विस सैंटर से फोन आया कि मदर बोर्ड भी खराब है और उन्हें नया फोन लेना चाहिए जो रिपेयरिंग की कीमत का ही मिल जाएगा। मधुसूदन ने वारंटी के हिसाब से फोन ठीक करने या पूरी कीमत वापस करने के लिए कहा। जब उन्हें कम्पनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जिला कंज्यूमर विवाद निवारण फोरम में शिकायत की। 2 साल तक चले केस में कम्पनी ने कहा कि फोन में आई खराबी वारंटी के तहत नहीं आती। हालांकि, फोरम ने पाया कि फोन एक साल के वारंटी पीरियड में जो रिपेयरिंग चार्ज कम्पनी ने लिया वह गलत था।

मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक: क्या मिलेगा सस्ते कर्ज का तोहफा

नई दिल्ली 6 फरवरी (ए)। रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समीक्षा की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। एम.पी.सी. की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेट को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रख सकता है। ऐसे में कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कम है।

7 फरवरी को आएगा समीक्षा का ब्योरा: वर्ष 2017-18 की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) की 6 और 7 फरवरी को बैठक होगी। केंद्रीय बैंक समीक्षा का ब्योरा बुधवार

दोपहर जारी करेगा। आर.बी.आई. ने दिसंबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका को देखते हुए मानक नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 6.7 प्रतिशत कर दिया। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में नीतिगत दर रेपो 0.25 प्रतिशत कम कर 6 प्रतिशत कर दिया जो छह साल का न्यूनतम स्तर है।

दरों में कटौती की उम्मीद नहीं : बैंक प्रमुखों तथा विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति में तेजी की आशंका को देखते हुए रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार नीतिगत दर को यथावत रख सकता है।

दिसंबर में महंगाई रही 5.21 फीसदी: फूड आयटम की कीमतें बढ़ने के कारण दिसंबर माह में खुदरा महंगाई 5 फीसदी को पार कर 5.21 फीसदी तक पहुंच गई। वहीं नवंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई 4.88 फीसदी और नवंबर में यह 3.41 फीसदी थी।